

प्रेषक,

इन्दिरा आशीष,  
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,  
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

महानिबन्धक,  
मा0 उत्तरांचल उच्च न्यायालय,  
नैनीताल ।

न्याय विभाग :

देहरादून : दिनांक : 13 सितम्बर, 2006

विषय: सिविल जज (जू.डि.) न्यायालय, खटीमा, जिला उधमसिंह नगर के अवासीय एवं अनावसीय भवनों के निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 1965/यू.एच.सी./एडमिन/निर्माण/2005 दिनांक 28 जुलाई, 2006 के संदर्भ में शासनादेश संख्या 98-दो(1)/छत्तीस(1)/न्याय अनुभाग/2004, दिनांक 11 फरवरी, 2005 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सिविल जज (जू.डि.) न्यायालय, खटीमा, जिला उधमसिंह नगर के अवासीय एवं अनावसीय भवनों के निर्माण हेतु टी०ए०सी० द्वारा अनुमोदित लागत रु0 3,73,40,000.00 के विपरीत स्वीकृत हेतु अवशेष धनराशि रु0 2,70,28,000.00 में से रु0 1,00,00,000.00 (रुपये एक करोड़ मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए इतनी ही धनराशि व्यय किये जाने की महामहिम राज्यपाल निम्न शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं :-

- (1) कार्य कराने से पूर्व समस्त कार्यों के विस्तृत आगणन एवं मानचित्र गठित कर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जाय, तदोपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय ।
- (2) एकमुश्त प्राविधानों का विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राप्त की जाय ।
- (3) उपर्युक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन दी जाती है कि व्यय से पूर्व बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, स्टोर पर्चेज रूल्स, मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत आदेश एवं तद्विषयक अन्य आदेशों का अनुपालन किया जाय । कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी/ अधिशासी अभियन्ता पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे ।
- (4) कार्य कराने से पूर्व स्थल की भली-भांति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भुगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें एवं निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण रिपोर्टों के अनुरूप ही कार्य किया जाय ।
- (5) निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित किया जाय ।
- (6) आगणन में धनराशि जिस मद हेतु स्वीकृत की गई है, उसी मद में व्यय की जाय । एक मद की राशि दूसरी मद में किसी भी दशा में व्यय न की जाय ।
- (7) आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा ।
- (8) निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला में टेस्टिंग करा लिया जाय तथा

- (9) कार्य को स्वीकृत लागत में ही पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा की स्थिति में लागत के पुनरीक्षण के लिए शासन द्वारा कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी।
  - (10) उक्त धनराशि का आहरण दो समान किशतों में किया जायेगा और प्रथम किस्त का पूर्ण उपयोग करने के बाद ही दूसरी किशत का आहरण कोषागार से किया जायेगा।
  - (11) स्वीकृत की जा रही धनराशि का 31.3.2007 तक पूर्ण उपयोग कर वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।
- 2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006-2007 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-04 के अन्तर्गत लेखा-शीर्षक "4059-लोकनिर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय-60-अन्य भवन-051-निर्माण-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना-03-न्यायिक कार्यों हेतु भवनों का निर्माण-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त अनुभाग-5 के अशासकीय संख्या-496/XXVI(1)/2006, दिनांक 21.8.2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(इन्दिरा आशीष)

सचिव।

संख्या- 34-दो(1)/XXXVI(1)/2005-51-दो(1)/04-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), औबराय बिल्डिंग, उत्तरांचल, माजरा, देहरादून।
2. जिला न्यायाधीश, उधमसिंह नगर।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, उधमसिंह नगर।
4. परियोजना प्रबन्धक, यूनिट-37 कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजायन सर्विसेज उ.प्र. जल निगम, उधमसिंहनगर।
5. नियोजन विभाग, उत्तरांचल शासन।
6. वित्त अनुभाग-5, उत्तरांचल शासन।
7. एन०आईसी०/सम्बन्धित सहायक/गार्ड फाईल

आज्ञा से,

(आलोक कुमार वर्मा)

( आलोक कुमार वर्मा )

अपर सचिव।